



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 90]
No. 90]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 29, 1984/चैत्र 9, 1906
NEW DELHI THURSDAY, MARCH 29, 1984/CHAITRA 9, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1984

सा. का. नि. 236(अ).—लोक ऋण नियमावली, 1946 के
नियम 4 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि
लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के
खंड (2) के उप-खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए सरकारी प्रतिभूति
का प्ररूप (फार्म) निम्नलिखित होगा, अर्थात् :—

“प्ररूप

भारत सरकार

7.75 प्रतिशत ऋण 1991—विशेष प्रतिभूति

संख्या ————— दिनांक —————

भारत के राष्ट्रपति एतद्वारा इस नोट के निर्गम की तारीख
से सात वर्ष पूरे हो जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक का रूप
(—————रूप)
की राशि अदा करने का दायित्व देते हैं ।

2. उपर्युक्त राशि पर इस नोट की तारीख से इस नोट के
सन्मोचन की तारीख के ठीक पहले की तारीख तक 7.75 प्रतिशत
प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा । ब्याज छमाही आधार
पर प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर और 31 मार्च को अदा किया
जाएगा ।

3. यह नोट अपरक्राम्य है ।

[संख्या एफ. 4(1)-डब्ल्यू. एण्ड एस./1

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 29th March, 1984

G.S.R. 236(E).—In exercise of the powers
conferred by clause (b) of rule 4 of the Public
Debt Rules, 1946, the Central Government here-
by specifies that the following shall be the form
of Government security for the purposes of sub-

clause (b) of clause (2) of section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944), namely :—

“FORM

GOVERNMENT OF INDIA

7.75% Loan 1991—Special Security

No..... dated the

The President of India hereby promises to pay to the Reserve Bank of India on expiry of seven years from the date of this Note the sum of Rs..... (Rupees

2. Interest at the rate of 7.75% per annum would be paid on the aforesaid amount from the date of this Note to the date immediately preceding the date on which the Note is discharged. Interest would be paid half-yearly on the 30th September and 31st March each year.

3. This Note is non-negotiable.

[No. F. 4(1)-W & M/84]

सा. का. नि. 237(अ).—लोक ऋण नियम, 1946 के नियम 4 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खंड (2) के उप-खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए सरकारी प्रतिभूति का प्ररूप (फार्म) निम्नलिखित होगा, अर्थात् :—

“प्ररूप

भारत सरकार

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक—7.75 प्रतिशत विशेष प्रतिभूति
संख्या ————— विनांक —————

भारत के राष्ट्रपति एतद्वारा —————
————— को मांग करने पर —————
————— रुपए (रुपए) की राशि अदा करने का वचन देते हैं ।

2. उपर्युक्त राशि पर इस नोट की तारीख से इस नोट के उन्मोचन की तारीख के ठीक पहले की तारीख तक 7.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा । ब्याज छमाही आधार पर प्रत्येक वर्ष ————— सितम्बर और ————— मार्च को अदा किया जाएगा ।

3. यह नोट अपरक्राम्य है ।

[संख्या एफ. 4(4)-डब्ल्यू. एण्ड एम./84]

G.S.R. 237(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of rule 4 of the Public Debt Rules, 1946, the Central Government hereby specifies that the following shall be the form of Government security for the purposes of sub-

clause (b) of clause (2) of section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1844), namely :—

“FORM

GOVERNMENT OF INDIA

Industrial Development Bank of India —7.75% Special Security.

No.....dated the.....

The President of India hereby promises to pay to.....on demand the sum of Rs.....(Rupees.....)

2. Interest at the rate of 7.75% per annum would be paid on the aforesaid amount from the date of this Note to the date immediately preceding the date on which the Note is discharged. Interest would be paid half yearly on September and March each year.

3. This Note is non-negotiable.

[No. F. 4(4)-W&M/84]

सा. का. नि. 238(अ).—लोक ऋण नियम, 1946 के नियम 4 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खंड (2) के उप-खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए सरकारी प्रतिभूति का प्ररूप (फार्म) निम्नलिखित होगा, अर्थात् :—

“प्ररूप

भारत सरकार

भारतीय यूनिट ट्रस्ट—विशेष प्रतिभूति

संख्या ————— विनांक —————

भारत के राष्ट्रपति इस नोट के निर्गम की तारीख से आठ वर्ष पूरे हो जाने पर अथवा इस नोट के निर्गम की तारीख से तीन वर्ष पूरे हो जाने के बाद किसी ऐसी पहले की तारीख के, जिस पर भारत सरकार सहमत हो,
————— को ————— रुपए (रुपए) की राशि अदा करने का वचन देते हैं ।

2. उपर्युक्त राशि पर इस नोट के निर्गम की तारीख से इस नोट के उन्मोचन की तारीख के ठीक पहले की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा । ब्याज छमाही अदायगियों के रूप में दिया जाएगा ; पहली अदायगी इस नोट के निर्गम की तारीख से छः महीने समाप्त होने पर शुरू होगी ।

3. यह नोट अपरक्राम्य है ।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक ।”

[संख्या एफ. 4(6)-डब्ल्यू. एण्ड एम./84]

ए. रंगाचारी, संयुक्त सचिव

G.S.R. 238(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of rule 4 of the Public Debt Rules, 1946, the Central Government hereby specifies that the following shall be the Form of Government security for the purposes of sub-clause (b) of clause (2) of section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944), namely :—

“FORM

GOVERNMENT OF INDIA

Unit Trust of India—Special Security

No. dated the.....

The President of India hereby promises to pay to
on the expiry of eight years from the date of issue of this note or such earlier date after the expiry of three years from the date of issue of

this note as the Government of India may agree, the sum of Rs. (Rupees.....)

2. Interest at the rate of 9% per annum would be paid on the aforesaid amount from the date of issue of this Note to the date immediately preceding the date on which the Note is discharged. Interest would be paid by half-yearly payments, the first payment commencing on the expiry of six months from the date of issue of this note.

3. This Note is non-negotiable.

By order of the President of India

Governor

Reserve Bank of India.”

[No. F. 4(6)-W&M|84]

A. RANGACHARI, Jt. Secy.

